

भारत के चुनावी परदृश्य में बदलाव

परलिमिंस के लिये: [भारत नरिवाचन आयोग, पंजीकृत गैर-मान्यता पराप्त राजनीतिक दल, वीवीपीएटी, लोक प्रतनिधित्व अधनियम 1950, लोक प्रतनिधित्व अधनियम, 1951, CAG, सूचना का अधिकार अधनियम, 2005, वधिआयोग।](#)

मेन्स के लिये: स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनाव सुनश्चिति करने में भारत के नरिवाचन आयोग की भूमिका, हालिया चुनावी सुधार और चुनावी अखंडता को मज़बूत करने के लिये आवश्यक अतरिकित उपाय।

स्रोत: PIB

चर्चा में क्यों?

[भारतीय नरिवाचन आयोग \(ECI\)](#) ने चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने, मतदाता भागीदारी को सुदृढ़ करने और भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे की वशिवसनीयता बनाए रखने के लिये कई पहल की हैं।

भारत की चुनाव प्रक्रिया को मज़बूत करने के लिये कौन-से प्रमुख सुधार किये गए हैं?

- मतदाता सूची प्रबंधन: चुनाव आयोग ने [476 नषिकरयि पंजीकृत गैर-मान्यता पराप्त राजनीतिक दलों \(RUPPs\)](#) की पहचान की है, ताकयिह सुनश्चिति कयिा जा सके क राजनीतिक दलों की सूची सटीक और अद्यतन बनी रहे।
 - चार राज्यों में उपचुनावों से पहले वशिव संक्षपित संशोधन के माध्यम से मतदाता सूचयिों को संशोधति कयिा गया, जो दो दशकों में इस तरह की पहली कवायद थी।
 - इसके अलावा, बिहार में [मतदाता सूची](#) का वशिव गहन पुनरीक्षण कयिा गया ताकयिह सुनश्चिति कयिा जा सके ककिई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र नाम न रह जाए।
 - देश भर में डुप्लिकेट [EPIC \(मतदाता\) कार्ड](#) समाप्त कर दयि गए, जसिसे प्रत्येक मतदाता को एक वशिषिट पहचान संख्या मलि गई और मतदाता सूचयिों में त्रुटयिों कम हो गई।
- प्रौद्योगिकी-संचालति पारदर्शिता और नगिरानी: [चुनाव आयोग ने ECINET नामक एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म](#) लॉन्च कयिा है, जो नरिवाचकों, मतदाताओं, चुनाव अधिकारयिों और राजनीतिक दलों द्वारा उपयोग कयि जाने वाले 40 से अधिक अनुप्रयोगों और वेबसाइटों को एक साथ लाता है।
 - नरिवाचन क्षेत्र स्तर पर चुनाव संबंधी डेटा को अधिक सुलभ बनाने के लयि डिजिटल इंडेक्स कार्ड और रपिर्ट शुरु की गई, जसिसे सूचति नरिणय लेने में सहायता मलि।
 - प्रमुख गतिविधयिों पर नजर रखने तथा मतदान प्रक्रयिा को सुचारू रूप से तथा बनिा कसिी उल्लंघन के संपन्न कराने के लयि मतदान केंद्रों की 100% वेबकास्टगि लागू की गई।
- बूथ स्तर पर सुधार: क्षेत्र स्तर पर पारदर्शिता में सुधार लाने और चुनाव प्रक्रयिा में जनता का वशिवास बढ़ाने के लयि बूथ स्तर के अधिकारयिों (BLO) को मानक फोटो पहचान पत्र जारी कयि गए।
 - मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1,200 तक सीमति कर दी गई, जसिसे भीड़ कम हुई, कतारें छोटी हुई और ऊँची आवासीय परसिरों और सोसाइटयिों में अतरिकित बूथ बनाने की अनुमतिमलि।
- मतदाता सत्यापन और सटीकता: फॉर्म 17C (मतदान केंद्र पर दर्ज मतों का लेखा-जोखा) और EVM डेटा के बीच बेमेल के मामलों में, और जहाँ भी मॉक पोल डेटा मटियायिा नहीं गया था, वहाँ [VVPAT](#) प्रची की गनिती अनवार्य रूप से लागू की गई, ताकमतिगणना की सटीकता और वशिवसनीयता सुनश्चिति की जा सके।

भारत की नरिवाचन प्रक्रयिा के सामने प्रमुख चुनौतयिाँ कयिा हैं?

- चुनाव वयय में वृद्धि: चुनावों में वास्तविक वयय और कानूनी रूप से नरिधारति सीमा के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है।
 - उम्मीदवार और राजनीतिक दल अक्सर नरिधारति खर्च सीमा से अधिक वयय कर देते हैं, जसिसे वयय की कम रपिर्टगि और छायात्मक

वित्तपोषण (shadow financing) होता है।

- यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और काले धन के निर्माण में योगदान करता है।

- **राजनीति का अपराधीकरण:** कई आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ते और जीतते हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञ-अपराधी संबंध धन एवं शक्ति पर आधारित होता है।
 - वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में, 543 नए निर्वाचन सांसदों में से 251 (46%) के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं।
- **मतदाता अधिकार हनन और मतदान प्रतिशत की समस्याएँ:** सुदृढ़ चुनावी मशीनरी के बावजूद, नकली मतदान, मतदाता सूची में नाम न होना और नगरीय क्षेत्रों में कम मतदान जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
 - आंतरिक प्रवासी, वरिष्ठ नागरिक और विशेष आवश्यकता वाले लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने में बाधाओं का सामना करते हैं, जिससे समावेशिता अप्रभावी बन जाती है।
- **फ्रीबीज/मुफ्तखोरी की राजनीति और लोकलुभावन वादे:** चुनावों के दौरान अस्थायी फ्रीबीज/मुफ्त सुविधाओं की बढ़ती संस्कृत वित्तीय अनुशासन और ज़िम्मेदार शासन को अप्रभावी करती है।
 - मतदाता दीर्घकालिक विकासात्मक एजेंडों की बजाय तात्कालिक लाभों से प्रभावित होते हैं।
 - स्पष्ट दिशा-निर्देशों की अनुपस्थिति के कारण कल्याणकारी योजनाओं और वित्तीय लोकलुभावनवाद के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है।
- **चुनावी हिसा और बूथ-स्तरीय संवेदनशीलताएँ:** यद्यपि कम हुई है, फिर भी कभी-कभी हिसा, मतदाताओं को डराने-धमकाने की घटनाएँ और बूथ-स्तरीय मतदान पैटर्न का खुलासा अभी भी होता है।
 - संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में अपर्याप्त बूथ प्रबंधन स्वतंत्र और नृपक्ष चुनावों को कमजोर करता है।
 - टोटलाइज़र मशीनों की अनुपस्थिति समुदायों को चुनाव-परांत प्रतिशोध के खतरे के प्रति और अधिक असुरक्षित बनाती है।
- **प्रौद्योगिकीय और साइबर खतरे:** सोशल मीडिया पर डीपफेक, भ्रामक जानकारी और एल्गोरिदम-आधारित हेर-फेर का उभरना चुनावी नृपक्षता के लिये एक नई तरह का खतरा प्रस्तुत करता है।
- **मतदाता सूची में हेर-फेर:** मतदाता सूची में छल-कपट के आरोप और विभिन्न राज्यों में दोहराए गए EPIC नंबर मतदाता सूची की विश्वसनीयता और जनविश्वास को कमजोर करते हैं।
- **दल-आंतरिक लोकतंत्र की कमी:** राजनीतिक दल अत्यधिक केंद्रीकृत एवं अपारदर्शी तरीके से कार्य करते रहते हैं, जहाँ वंशवादी प्रभुत्व, पारदर्शी उम्मीदवार चयन की कमी तथा जवाबदेही की दुर्बलता बनी रहती है।
 - यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और वास्तविक नेतृत्व के उभरने में बाधा उत्पन्न करता है।



भारत में चुनाव सुधार

चुनाव सुधार, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये किये गये बदलाव हैं।

वर्ष 1996 से पूर्व में हुए चुनाव सुधार

- **आदर्श आचार संहिता (1969):** राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये चुनाव संबंधी दिशा-निर्देश
- **61वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1988):** मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना
- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) (1989):** अलग-अलग रंगीन मतपेटियों से मतपत्रों में और बाद में EVM में परिवर्तन
- **बूथ कैप्चरिंग (1989):** ऐसे मामलों में मतदान स्थगित करने या चुनाव रद्द करने का प्रावधान
- **मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) (1993):** मतदाता सूची पंजीकृत मतदाताओं को EPIC जारी करने का आधार है।
- **भारत का निर्वाचन आयोग- एक बहु-सदस्यीय निकाय (1993):** मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आलावा अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

वर्ष 1996 का चुनाव सुधार

- **उप-चुनाव के लिये समय-सीमा:** विधानसभा में किसी भी रिक्ति के 6 माह के अंदर चुनाव को अनिवार्य किया गया
- **उम्मीदवारों के नामों की सूची:** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लिस्टिंग के लिये 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है:
 - मान्यता प्राप्त और पंजीकृत-गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
 - अन्य (स्वतंत्र)
- **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के आधार पर अपमान करने पर अयोग्यता:** 6 वर्ष के लिये चुनाव में अयोग्यता हो सकती है:
 - भारत के राष्ट्रीय ध्वज, संविधान का अपमान करना या राष्ट्रगान गाने से रोकना

वर्ष 1996 के पश्चात् चुनाव सुधार

- **प्रॉक्सी वोटिंग (2003):** सेवा मतदाता सशस्त्र बलों और सेना अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बल चुनाव में प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन (2003):** जनता को संबोधित करने के लिये चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का समान बंटवारा।
- **EVM में ब्रेल संकेत विशेषताओं का परिचय (2004):** दृष्टिबाधित मतदाताओं को बिना किसी परिचारक के अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान करना

वर्ष 2010 के चुनाव सुधार

- विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार (2010)
- मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन (2013)
- नोटा विकल्प का परिचय (2014)
- **मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) (2013):** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये EVM के साथ VVPAT की शुरुआत
- **EVM और मतपत्रों पर उम्मीदवारों की तस्वीरें (2015):** उन निर्वाचन क्षेत्रों में भ्रम से बचने के लिये जहाँ उम्मीदवारों के नाम एक समान होते हैं
- **चुनाव बॉन्ड की शुरुआत (2017 बजट):** राजनीतिक दलों के लिये नकद दान का एक विकल्प
 - SC द्वारा असंवैधानिक घोषित (2024)
- इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) का आरंभ (2021)
- दिव्यांगजनों और 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिये होम वोटिंग (2024)

महत्वपूर्ण समितियाँ/आयोग

समितियाँ/आयोग	वर्ष	उद्देश्य
■ तारकुंडे समिति	1974	■ जय प्रकाश नारायण (जेपी) द्वारा "संपूर्ण क्रांति" आंदोलन के दौरान।
■ दिनेश गोस्वामी समिति	1990	■ चुनाव सुधार
■ वोहरा समिति	1993	■ अपराध और राजनीति के बीच गठजोड़ पर
■ इन्द्रजीत गुप्ता समिति	1998	■ चुनावों का राज्य वित्त पोषण
■ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग	2007	■ शासन में नैतिकता पर रिपोर्ट (वीरप्पा मोड्ली की अध्यक्षता में)
■ तन्खा समिति (कोर कमेटी)	2010	■ निर्वाचन विधि और चुनाव सुधारों के संपूर्ण पहलू पर विचार करना।



Drishti IAS

भारत के चुनावी प्रणाली को और अधिक सशक्त करने के लिये क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- **चुनावी वित्त सुधार:** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सफ़ाईनुसार वैध व्ययों की प्रतिलिपि सहित आंशिक राज्य वित्तपोषण लागू करना; निर्धारित सीमा से अधिक दान का अनिवार्य डिजिटल प्रकटीकरण सुनिश्चित करना; गुमनाम कॉर्पोरेट वित्तपोषण पर नियंत्रण हेतु प्रभावी विनियमन; सुदृढ़ CAG/ECI ऑडिट तंत्र की स्थापना तथा धनबल पर अंकुश और मतदाता विश्वास को प्रबल बनाने के लिये एक सार्वजनिक चुनाव व्यय पोर्टल की व्यवस्था करना।
 - इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लाने पर भी विचार किया जाना चाहिये।
- **आंतरिक पार्टी लोकतंत्र का संवर्द्धन:** राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, कति अधिकांश दल अब भी बंद, परिवार-प्रधान इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं।
 - कानून में नियमित आंतरिक चुनाव, पारदर्शी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया और ऑडिटेड पार्टी संविधान को अनिवार्य किया जाना चाहिये।
 - इसके अतिरिक्त, वधिआयोग की वर्ष 1999 की रिपोर्ट ने आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को सुनिश्चित करने हेतु एक नियामक ढाँचा प्रस्तावित किया था।
- **डिजिटल अभियान और डीपफेक को विनियमित करना:** सभी राजनीतिक विज्ञापनों में (प्रायोजक, वित्तपोषण स्रोत और भूलक्ष्यीकरण) से संबंधित पहचान योग्य प्रकटीकरण लेबल को अनिवार्य किया जाए।
 - वास्तविक समय में सोशल मीडिया को स्कैन करने के लिये एक राष्ट्रीय डीपफेक डिटेक्शन सेल (आईआईटी और सीईआरटी-इन के साथ) की स्थापना करनी चाहिये।
 - अनुपालन न करने वाले प्लेटफॉर्म के लिये दंड के साथ सख्त नषिकासन प्रोटोकॉल लागू करना चाहिये। एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह, डीपफेक और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिये मतदाता साक्षरता अभियान शुरू करना चाहिये।
- **ECI को मज़बूत करना:** चुनाव आयोग को पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता दी जाए और उसका बजट सीधे भारत की संघीय नधि से आवंटित किया जाए।
 - **स्थायी कर्मियों से युक्त क्षेत्रीय चुनाव आयोग प्रकोष्ठ,** भारत के विशाल निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावी और सुदृढ़ नगरानी सुनिश्चित कर सकते हैं।
 - संसदीय समितियों द्वारा चुनावी प्रक्रियाओं की नियमिता निष्पादन लेखापरीक्षा से विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संरक्षक के रूप में भारत निर्वाचन आयोग को मज़बूती मिलेगी।
 - **चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने, हितों के टकराव को समाप्त करने, केंद्र एवं राज्य सरकारों पर निर्भरता घटाने और स्वायत्तता व निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु** ईसीआई को अधिकारियों का एक स्थायी एवं स्वतंत्र कैंडर स्थापित करना चाहिये।
- **निर्वाचन प्रक्रिया सुधार:** बूथ-स्तरीय मतदान पैटर्न के खुलासे को रोकने के लिये पूरे देश में टोटलाइज़र मशीनों के उपयोग का विस्तार किया जाएगा, तार्किक वोटों को बूथ स्तर पर मंजूर किया जा सके।
 - एक समान मतदाता सूची सुनिश्चित करनी चाहिये, आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना चाहिये तथा समान अवसर बनाए रखने और मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने के लिये अभियान की अवधि को सीमित करना चाहिये।
- **समकालिक एवं सतत चुनावों की ओर: "एक राष्ट्र, एक चुनाव"** की अवधारणा को स्थानीय और राज्य स्तर पर प्रायोगिक रूप से लागू किया जाए। दोहराव कम करने के लिये एक स्थायी राष्ट्रीय मतदाता सूची और एक समान मतदाता पहचान-पत्र लागू करने चाहिये।
 - एक साथ होने वाले चुनावों से होने वाली बचत को शासन की ओर पुनर्निर्देशित करना चाहिये तथा धीरे-धीरे लागत-कुशल, समय-कुशल और शासन-अनुकूल चुनावों के लिये एक निश्चित चुनावी कैलेंडर लागू करना चाहिये।

परश्न: “११११११ १११११११११११ १११११ १११११११ ११११, १११११ १११११११ १११११११११ ११११ ११ ११११११११११ ११११११११११११ १११११ १११११११११११११११११११ ११ ११११११११११ १११११ ११ ११११११११ १११११” हालिया वविादों एवं सवतंतर नरिवाचन आयोग की आवश्यकता के संदरभ में इस कथन की समालोचनातमक समीकषा कीजयि ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न 1. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजएि: (2021)

1. भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोक सभा चुनाव में तीन नरिवाचन-क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है।
2. 1991 के लोक सभा चुनाव में श्री देवी लाल ने तीन लोक सभा नरिवाचन-क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था।
3. वर्तमान नयिमें के अनुसार, यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोक सभा चुनाव में कई नरिवाचन-क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसकी पार्टी को उन नरिवाचन-क्षेत्रों के उप-चुनावों का खर्च उठाना चाहिए, जनिहें उसने खाली किया है बशर्ते वह सभी नरिवाचन-क्षेत्रों से वजियी हुआ हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) 2 और 3

उत्तर: (b)

??????

प्रश्न 1. वभिनिन समतियिों द्वारा सुझाए गए, एवं "एक राष्ट्र-एक चुनाव" के वशिषिट संदर्भ में, चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण कीजयि। (2024)

प्रश्न 2. लोक प्रतनिधितिव अधनियिम, 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य वधियकि के सदस्यों के चुनाव से उभरे वविादों के नरिणय की प्रक्रिया का वविचन कीजयि। कनि आधारों पर किसी नरिवाचति घोषति प्रत्याशी के नरिवाचन को शून्य घोषति किया जा सकता है? इस नरिणय के वरिद्ध पीड़ति पक्ष को कौन-सा उपचार उपलब्ध है? वाद वधियिों का संदर्भ दीजयि। (2022)